

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख, 1940 (श॰)

संख्या- ४४४ राँची, मंगलवार, 24 अप्रैल, 2018 (ई॰)

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,

अधिसूचना 17 अप्रैल, 2018

संख्या-01/स्था॰-1-01/2006/04-- राज्य सरकार के कर्मियों को संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने संबंधी वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2981/वि॰ दिनांक 1 सितम्बर, 2009 के आलोक में दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निर्वाचन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित तीन पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में तृतीय एम०ए०सी०पी० लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र॰सं॰	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं	नियुक्ति की	तृतीय संशोधित वित्तीय उन्नयन के
	पदनाम	तिथि	स्वीकृति प्रदान किये जाने की
			तिथि/वेतनमान
1	2	3	4
1.	श्री अरूण कुमार तिवारी, सेवानिवृत	18.01.1984	18.01.2014 PD W 27429 (7999 CR 9799)
	उप निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला ।		PB-IV, 37400-67000, GP 8700/-
2.	श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत उप	18.01.1984	18.01.2014
	निर्वाचन पदाधिकारी, साहेबगंज ।		PB-IV, 37400-67000, GP 8700/-
3.	श्री बिपिन बिहारी, उप निर्वाचन	08.04.1987	08.04.2017
	पदाधिकारी, धनबाद ।		PB-IV, 37400-67000, GP 8700/-

- 2. यह MACP पूर्णत: औपबंधिक है और निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन देय है ।
 - (क) यह वित्तीय उन्नयन वैयक्तिक होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है।
 - (ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के अंतर्गत वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2981 दिनांक 1 सितम्बर, 2009 में निहित शर्त्तों के आलोक में औपबंधिक रूप से किया जाएगा।
 - (ग) यह MACP मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के आधर पर स्वीकृत किया गया है। भविष्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है अथवा गणना या टंकण भूल के कारण गलत या अधिक भुगतान हो जाता है या अंकेक्षण द्वारा आपत्ति की जाती है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारी से एक मुश्त में कर ली जायेगी।
- 3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2981/वि॰ दिनांक 1 सितम्बर, 2009 के अन्य सभी प्रावधान/शर्तें उक्त वित्तीय उन्नयन पर यथावत रूप से लागू होंगे ।
 - 4. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-**संजय प्रसाद श्रीवास्तव,** सरकार के अवर सचिव।
